www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी खबर

वर्ष – 04 | अंक – 254 | जौनपुर सोमवार, 04 मई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

महाराष्ट्र को काऊ बेल्ट बनाना महायुति का मकसद : हर्षवर्धन सपकाल

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन एक सुनियोजित साजिश के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू, फुले और अंबेडकर के आदर्शों पर बने प्रगतिशील महाराष्ट्र को काउ बेल्ट में बदलने की कोशिश कर रहा है। दरअसल, काऊ बेल्ट उत्तर और मध्य भारत के उन राज्यों को कहा जाता है, जहां हिंदी प्रमुख भाषा है और गाय की उच्च धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता है। महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस के मौके पर शुक्रवार को आयोजितसमारोह में सपकाल ने नागरिकों से उन ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया जो सांप्रदायिक और जाति–आधारित संघर्ष भड़काकर श्महाराष्ट्र की संस्कृतिश (महाराष्ट्र धर्म) को दूषित करने की कोशिश कर रही हैं। सपकाल ने जनता और कामगारों को अपनी शुभकामनाएं देने के बाद राज्य की समृद्ध विरासत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह धरती छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों से बनी है और यह भी जोड़ा कि यह वारकरी संप्रदाय की समानता की शिक्षाओं से धन्य धरती है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि यह पहचान खतरे में है।

रामदास अठावले ने जाति जनगणना के लाभों का ब्योरा दिया

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र में शुक्रवार को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर 2027 की जनगणना के स्व–गणना की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने इस बात पर जोर दिया कि जाति जनगणना से सरकार को प्रत्येक जाति की सहायता करने में मदद मिलेगी। स्व–गणना प्रक्रिया 1 से 15 मई, 2026 तक चलेगी, जिसके बाद 16 से 14 जून, 2026 तक घर–घर जाकर जनगणना की जाएगी। इस दौरान जनगणना कर्मी घर–घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।आईएएनएस से बात करते हुए अठावले ने कहा कि जनगणना विभाग के अधिकारी आज बैठक में आए थे। मैंने सभी नागरिकों से इस जनगणना के संचालन में सहयोग करने की अपील की है। इससे हमें महाराष्ट्र की जनसंख्या के साथ–साथ पूरे देश की जनसंख्या का भी पता चलेगा। उन्होंने बताया कि जनगणना प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार ने जाति के आधार पर भी जनगणना कराने का निर्णय लिया है।उन्होंने कहा कि पहले जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही शामिल किया जाता था। लेकिन इस बार जनगणना प्रत्येक धर्म और जाति के आधार पर की जाएगी। जाति जनगणना के लाभों का वर्णन करते हुए।

लद्दाख में डेयरी और सहकारिता को बढ़ावा, अमित शाह ने कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लद्दाख के कारगिल में विभिन्न डेयरी अवसंरचना और सहकारी पहलों का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पहलें क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रोजगार को नई दिशा देंगी। कारगिल में 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया गया, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 10,000 लीटर दूध प्रोसेसिंग की होगी। अमित शाह ने कहा कि इस प्लांट से विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इस अवसर पर EMCS ऐप भी लॉन्च किया

गया, जिसके माध्यम से दुग्ध उत्पादक अपने दूध के लेनदेन और भुगतान का पूरा विवरण एक ही प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे। इससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों में सुधार होगा। लद्दाख मिल्क फेडरेशन और मदर डेयरी के बीच हुए समझौता ज्ञापन से लद्दाख के दुग्ध उत्पादों की देशभर के बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी, जिससे स्थानीय उत्पादकों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। अमित शाह ने बताया कि 2014–15 में भारत का दूध उत्पादन 146 मिलियन टन था, जो अब 70% बढ़कर 248 मिलियन टन हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 वर्षों में 75,000 नई दुग्ध समितियां बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 21,000 समितियां पहले ही बनाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख में पश्मीना, ऑर्गेनिक उत्पादों और शहद से जुड़े क्षेत्रों में भी सहकारी संस्थाओं का गठन किया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विकास को नई गति मिली है। पहले जहां लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च होते थे, अब यह बढ़कर करीब 6,000 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने बताया कि 2019 के बाद लद्दाख में सड़कों, पुलों, मोबाइल टावरों और हेलीपैड की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

निराधार आरोपों की राजनीति कर अदालत पहुंचना टीएमसी की पुरानी प्रवृत्ति : सुधांशु त्रिवेदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया ब्रीफिंग में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे–जैसे चुनाव आगे बढ़ा, तृणमूल कांग्रेस का जनसमर्थन और मनोबल लगातार गिरता गया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ष्जैसे ही शांतिपूर्ण और हिंसा मुक्त मतदान संपन्न हुआ, टीएमसी के अंदर बेचौनी और घबराहट बढ़ने लगी और जब एग्जिट पोल के रुझान सामने आए तो ऐसा लगा कि उनका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है।सुधांशु त्रिवेदी ने टीएमसी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के फैसले को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अनर्गल और निराधार आरोपों के आधार पर कोर्ट जाना उनकी पुरानी आदत और बौखलाहट का प्रमाण है। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि पिछले 10–12 वर्षों में टीएमसी अलग–अलग अदालतों में 80 से ज्यादा बार जा चुकी है और हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप की मांग वाली टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है साथ ही कपिल सिब्बल द्वारा दायर याचिका को भी अदालत ने स्वीकार नहीं किया। सुधांशु त्रिवेदी ने एक और आरोप लगाते हुए कहा कि जब आईपैक कार्यालय पर छापा पड़ा था, तब पहली बार ऐसा हुआ कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंचीं। इससे यह संकेत मिलता है कि उन्हें अपने ही स्टाफ और करीबी सहयोगियों पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। पश्चिम बंगाल की कानून–व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में स्थिति बेहद खराब है।

मई की गर्मी से घबराने की जरूरत नहीं, सावधानियों से प्रभाव को किया जा सकता है नियंत्रित : डॉ. जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आम जनता को आश्वस्त किया है कि मई महीने में संभावित भीषण गर्मी को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मौसम पूर्वानुमान को सही ढंग से समझकर और सरल सावधानियां अपनाकर इसके प्रभाव को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। मंत्री ने लोगों से लू की भविष्यवाणी पर अनावश्यक प्रतिक्रिया न देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक हो सकता है, लेकिन यह स्थिति पूरे देश में एक समान नहीं रहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर–पूर्व और उत्तर–पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है, जबकि देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य या उससे कम रह सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार हिमालय की तलहटी, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में लू चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में सामान्य से 2–4 दिन अधिक लू चल सकती है। मंत्री ने बताया कि 8–14 मई और 22–28 मई के बीच तापमान अधिक रहने की संभावना है, जिससे उत्तर–पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में लू चल सकती है।

बंगाल व असम की जीत पर जयश्रीराम से गुंजायमान हुआ भाजपा कार्यालय

बांटे गये जीत के लड्डू, आतिशबाजी व ढोल नगाड़ो के बीच बना उत्सव का माहौल

बंगाल व असम की प्रचंड जीत पर सहादतगंज भाजपा कार्यालय में मना जश्न

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। बंगाल व असम में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर सहादतगंज स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जमकर जश्न मनाया। ढोल–नगाड़ों की गूंज और आतिशबाजी के बीच जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने एक–दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की। कार्यालय परिसर में उत्साह का माहौल देर तक बना रहा। इस दौरान जय श्री राम , भारत माता की जय, वंदे मातरम्क, के जय घोष से परिवेश गुंजायमान हो गया। इस दौरान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि यह विजय केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि देश में राष्ट्रवादी विचारधारा और विकास मॉडल की स्वीकार्यता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अब स्थिर, पारदर्शी और विकासोन्मुखी सरकार चाहती है। बंगाल की जनता ने वर्षों से चली आ रही अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति को नकारते हुए भाजपा के सुशासन को स्वीकार किया है।महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि बंगाल और असम की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जनता के विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बनने जा रही है, जो सुशासन और विकास की नई दिशा तय करेगी।जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन की मजबूती का परिणाम है कि भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिली है। उन्होंने इसे राष्ट्रवाद और विकास की विचारधारा की विजय बताते हुए कहा कि जनता ने तुष्टिकरण की राजनीति को नकार दिया है।महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह जीत भाजपा की नीतियों, कार्यशैली और जनसेवा के प्रति समर्पण की विजय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान हित और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरकृको जनता ने सराहा है। मौके

पर पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, अवधेश पाण्डेय बादल, कमला शंकर पाण्डेय, महानगर महामंत्री शैलेन्द्र कोरी, तिलकराम मौर्या, ब्लाक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष शिवेन्द्र सिंह, रवि सिंह, शिवम् शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष अखण्ड सिंह डिम्पल, कृष्ण कुमार पांडेय जिला महामंत्री राघवेंद्र पांडेय, शिवम सिंह,अशोक कसौधन, करुणाकर पाण्डेय, गिरीश पाण्डेय डिप्पुल, बाल कृष्ण वैश्य, हरभजन गौड, अरविंद सिंह, मनोज बर्मा, सुशील मिश्रा, अमित कुमार मिश्र, रवि सोनकर, शशि प्रताप सिंह, हेमंत जायसवाल, सर्वज्ञ सिंह, बब्लू मिश्र, जेपी श्रीवास्तव, ओमिश अग्रहरि सहित बडी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।

सरकार आरटीसी कर्मचारियों के सभी लंबित भुगतानों के निपटान के लिए प्रयासरत है : रेवंत रेड्डी

हैदराबाद, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार टीजीएसआरटीसी को आर्थिक रूप से मजबूत करने और पूरे संगठन के सुचारू संचालन के लिए कई कदम उठा रही है। राज्य सरकार आरटीसी कर्मचारियों की मांगों को हल करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आरटीसी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आरटीसी यूनियनों के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और घोषणा की कि आरटीसी कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल की अवधि का वेतन जारी किया जाएगा और हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री और अन्य अधिकारियों को हड़ताल की अवधि

के वेतन के भुगतान और मामलों को वापस लेने के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को आरटीसी ट्रेड यूनियन के नेताओं ने जुबली हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। यूनियन नेताओं ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने हेतु मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि संगठन के विकास को बढ़ावा देने, इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने, इसकी गरिमा को बनाए रखने और जनता को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि आरटीसी कर्मचारियों ने कांग्रेस को सरकार बनाने में सहयोग दिया और संघर्ष के दौरान कांग्रेस आरटीसी कर्मचारियों के साथ खड़ी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीसी के राजस्व में वृद्धि के लिए बसों की संख्या बढ़ाई गई है और कर्मचारियों की भर्ती की गई है। इसके अलावा, सरकार ने शमशाबाद में 150 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय मानक का बस टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया है और गजुलारामारम में बस टर्मिनल के निर्माण के लिए 100 एकड़ भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। डीजल बसों के बढ़ते वित्तीय बोझ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीसी मेट्रो रेल नेटवर्क से निर्बाध संपर्क स्थापित करने और अपने बेड़े में मिनी बसें शामिल करने के लिए 1,000 इलेक्ट्रिक बसें (ईवी) खरीद रही है।

किसानों को 60 प्रतिशत विकसित जमीन का मिलेगा लाभ : मोहन यादव

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर–पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना को तेज गति से आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके तहत किसानों को दी जाने वाली विकसित जमीन की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। परियोजना के पहले चरण का भूमि पूजन 3 मई को मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के नैनोद गांव स्थित सेक्टर–ए में करेंगे। शुक्रवार को जारी प्रेस नोट के अनुसार, पहले चरण की अनुमानित लागत 326.51 करोड़ रुपए है। इसी के साथ बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की शुरुआत होगी। इस परियोजना में किसानों को मिलने वाली विकसित जमीन की हिस्सेदारी 50 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। इस फैसले से किसानों का भरोसा बढ़ा है और वे स्वेच्छा से परियोजना में भागीदारी कर रहे हैं। इंदौर–पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस योजना के तहत 75 मीटर चौड़ी और 20 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों ओर 300–300 मीटर क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे।यह परियोजना 1,300 हेक्टेयर भूमि में फैली है और इसकी कुल अनुमानित लागत 2,360 करोड़ रुपए है। परियोजना के तहत औद्योगिक, व्यावसायिक और सेवा क्षेत्र के लिए आधुनिक बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के हित को प्राथमिकता देकर विकास और जनकल्याण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।

'घबराएं नहीं, यह सिर्फ टेस्ट अलर्ट है': सेल ब्रॉडकास्ट संदेश पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत ने शनिवार को स्वदेशी तकनीक के जरिए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा की शुरुआत की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय संचार व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह पहल नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने और आपदा के समय त्वरित सूचना सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है। सिंधिया ने स्पष्ट किया कि मोबाइल फोन पर आया अलर्ट भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का एक परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक के जरिए विकसित किया है। सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अलर्ट की फोटो साझा करते हुए लिखा कि यदि किसी के मोबाइल पर ऐसा संदेश आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह केवल परीक्षण के उद्देश्य से भेजा गया संदेश है। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली दूरसंचार विभाग के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र सी–डॉट द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सहयोग से विकसित की गई है। सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के जरिए आपदा या आपातकाल की स्थिति में स्थानीय भाषा और लोकेशन के आधार पर तुरंत अलर्ट भेजे जा सकेंगे। इससे नागरिकों तक सही समय पर सटीक जानकारी पहुंचाना संभव होगा।

अब मोदी तत्व और आरएसएस का इतिहास पढ़ेंगे छात्र, मैक्स वेबर के सिद्धांत से होगी तुलना

वडोदरा, (एजेंसी)। गुजरात के वडोदरा स्थित प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एक बड़ा बदलाव किया है। विश्वविद्यालय ने अपने समाजशास्त्र के सिलेबस में मोदी तत्व नाम का एक नया मॉड्यूल शामिल किया है। इस कोर्स के जरिए छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और समाज पर इसके प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास और सामाजिक योगदान को भी जगह दी गई है। समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह नया विषय एमए समाजशास्त्र के दो साल के कार्यक्रम में देशभक्ति का समाजशास्त्र शीर्षक के तहत पेश किया गया है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व शैली के साथ–साथ छत्रपति शिवाजी महाराज और सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय जैसे समाज सुधारकों के कार्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने पाठ्यक्रम के शैक्षणिक आधार को स्पष्ट करते हुए कहा, आप उन्हें पसंद करें या न करें, लेकिन आपको राजनीतिक क्षेत्र और नेतृत्व की भूमिका में पीएम मोदी पर चर्चा करनी ही होगी। वह एक ऐसे तत्व हैं जो लंबे समय तक बने रहेंगे। हम समाजशास्त्री मैक्स वेबर के करिश्माई नेतृत्व के सिद्धांत का अध्ययन करना चाहते थे, जो महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग में देखा गया था। उसी तरह का करिश्माई नेतृत्व पीएम मोदी में भी दिखाई देता है। यह एक वैज्ञानिक मामला है जिसकी जांच की आवश्यकता है।श डॉक्टर सिंह नीति आयोग की परियोजनाओं की निगरानी से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोदी तत्व के तहत मीडिया, डिजिटल राष्ट्रवाद, नागरिकता, असहमति, वैश्वीकरण और पहचान की राजनीति जैसे विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें चर्चा होगी कि वह इतने प्रसिद्ध क्यों हो रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता इतनी व्यापक क्यों है और लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के पीछे उनकी महानता क्या है? इस पाठ्यक्रम में नोटबंदी, डिजिटल क्रांति, फास्टैग और जल शक्ति मंत्रालय जैसी नीतियों का भी अध्ययन किया जाएगा। वीरेंद्र सिंह का मानना है कि ये नीतियां दर्शाती हैं कि प्रधानमंत्री जनता की जरूरतों को कितनी गहराई से समझते हैं। आरएसएस को पाठ्यक्रम में शामिल करने के पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जब छात्र नीति आयोग के प्रोजेक्ट के लिए सुदूर गांवों में सर्वेक्षण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आरएसएस से जुड़े लोग वहां योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

संपादकीय

दूरगामी परिणाम झेलने तैयार रहना चाहिए

आरबीआई ने जो कहा है, उसका सार है कि पश्चिम एशिया में युद्ध से सप्लाई शृंखला बाधित हो गई है, जिसके दूरगामी परिणाम झेलने के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। बैंक ने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है। महंगाई की तगड़ी मार फिर आ पड़ी है, जबकि अर्थव्यवस्था के सारे गुलाबी अनुमान गड़बड़ाते दिख रहे हैं– भारतीय रिजर्व बैंक ने जो कहा है, उसका यही सार है। संदेश यह है कि पश्चिम एशिया में युद्ध ने सप्लाई शृंखला को बाधित रखा दिया है, जिसके दूरगामी परिणाम झेलने के लिए सबको तैयार हो जाना चाहिए। बुधवार को अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 6.9 से घटा कर 6.7 प्रतिशत कर दिया, जबकि मुद्रास्फीति दर के पांच प्रतिशत तक पहुंचने की आशंका जता दी। इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे पांच जोखिमों का जिक्र किया। इनके मुताबिक होरमुज जलमार्ग में आई रुकावट के कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक आदि की उपलब्धता प्रभावित हो रही है, जिसका असर घरेलू उत्पादन पर पड़ेगा। खाड़ी क्षेत्र के प्रभावित होने की वजह से मालवाही जहाजों को लंबे समुद्री रूट लेने पर पड़ रहे हैं, जिससे माल भाड़े और माल डिलिवरी के समय में इजाफा हुआ है। मल्होत्रा ने चेताया कि जो शुरुआत में जिसे आपूर्ति झटका समझा गया है, मध्यम अवधि में वह मांग झटके में तब्दील हो सकता है। आपूर्ति बाधा से चीजें महंगी होंगी, जिससे बाजार में उनकी मांग घटेगी।

दरअसल, एमएमसीजी कंपनियों की मार्च की रिपोर्ट से संकेत मिला है कि असल महंगाई रिजर्व बैंक के अनुमान से भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके मुताबिक कच्चे तेल और अन्य इनपुट सामग्रियों की लागत में बढ़ोतरी के कारण इन कंपनियों ने मार्च में अपने उत्पादों की कीमत 7 से 8 फीसदी तक बढ़ा दी। जानकारों के मुताबिक वैश्विक तनाव जारी रहा, तो आने वाले महीनों में कीमतें 10 से 15 प्रतिशत तक और बढ़ सकती हैं। साथ ही रिजर्व बैंक ने आगाह किया है कि उर्वरकों की कमी का असर कृषि पैदावार पर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट खड़ा हो सकता है। आयात महंगा होने और पूंजी के बाहर जाने के कारण रुपया पहले से झटके खा रहा है। यानी संकट गहरा है, जिसका कोई समाधान सरकार के पास नहीं है।

पीएफबीआर की सफलता से शुरू होगी भारत की असली चुनौती

एस रघोत्तमभारत

समाचार भारत के विस्तार पर सबसे बड़ी बाधा विखंडनीय प्लूटोनियम भंडार है, विशेष रूप से 2035–2045 के बीच। वर्तमान में ब्रीडर कार्यक्रम सीमित संख्या में असुरक्षित रिएक्टरों से प्राप्त प्लूटोनियम पर निर्भर है। वहीं, भारत ने अपने सुरक्षित रिएक्टरों के लिए आयातित यूरेनियम से खर्च किया हुआ ईंधन जमा कर लिया है। यह महत्वपूर्ण प्लूटोनियम बेकार पड़ा है। अभी खत्म हुए अप्रैल की शुरुआत में भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (उन्नत परमाणु रिएक्टर–पीएफबीआर) की सफलता ने, जो बिजली उत्पादन के दौरान खर्च किए गए ईंधन की तुलना में अधिक नया ईंधन उत्पन्न करता है, एक बहुप्रतीक्षित उपलब्धि को चिह्नित किया है। इसने 1950 के दशक में होमी जहांगीर भाभा द्वारा परिकल्पित तीन स्तरीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में भारत के परिचालन प्रवेश का संकेत दिया है। यह उपलब्धि बहुत बड़ी है– दशकों तक प्रौद्योगिकी से वंचित रहने और संदेह व अनिश्चितता के बावजूद भारत ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के दम पर दृढ़ संकल्पित होकर व्यावसायिक पैमाने पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) का निर्माण किया है। फिर भी हमें सोशल मीडिया और यहां तक कि मुख्यधारा के मीडिया में व्याप्त प्रचार से परे देखना होगा। पीएफबीआर अंतिम लक्ष्य नहीं है। वास्तव में यह वह बिंदु है जहां कार्यक्रम अपने सबसे कठिन चरण में प्रवेश करता है। सवाल यह है कि क्या भारत इस कार्यक्रम को देश की बढ़ती ऊर्जा सम्बन्धी जरूरतों और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के लिए प्रासंगिक बनाए रखने के लिए औद्योगिक पैमाने पर तेजी से विकसित कर सकता है। भाभा के कार्यक्रम का तर्क अक्सर एक सुव्यवस्थित प्रगति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है– चरण 1 यूरेनियम रिएक्टर प्लूटोनियम को उप–उत्पाद के रूप में उत्पन्न करते हैंय चरण 2 एफबीआर उस प्लूटोनियम का उपयोग करके अधिक विखंडनीय पदार्थ का उत्पादन करते हैं और चरण 3 एक स्व–संचालित थोरियम चक्र पर चलता है। हमारी आज की अड़चन रिएक्टर नहीं बल्कि विखंडनीय भंडार–प्लूटोनियम है। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमानों और हालिया बयानों के अनुसार भारत के पास पीएफबीआर और दो अन्य 500 मेगावाट के रिएक्टर, एफबीआर 1 और 2 को शुरू करने एवं चलाने के लिए पर्याप्त पृथक प्लूटोनियम है। यदि आज अंतिम स्वीकृति व निधि मिल जाती है और निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये इकाइयां वर्ष 2035 तक चालू हो जाएंगी। हालांकि तैयार ईंधन की आपूर्ति यहीं समाप्त हो जाती है। ब्रीडर रिएक्टरों का नाम उनकी खपत से अधिक ईंधन उत्पादन करने की क्षमता के आधार पर रखा गया है लेकिन यह दर ब्रीडिंग अनुपात पर निर्भर करती है। मिश्रित ऑक्साइड (एमओएक्स) ईंधन का उपयोग करने वाले पीएफबीआर और एफबीआर 1 और 2 के लिए ब्रीडिंग अनुपात मामूली 1.03 से 1.05 है। इसके परिणामस्वरूप कूलिंग, रिप्रोसिसिंग और ईंधन में पुनरू निर्माण को ध्यान में रखते हुए सिस्टम के दोगुना होने का समय लगभग 30 वर्ष है। यानी प्रत्येक रिएक्टर को एक और इकाई शुरू करने के लिए पर्याप्त अधिशेष प्लूटोनियम उत्पन्न करने में इतना समय लगेगा। इस दर पर एफबीआर कार्यक्रम का विस्तार संभव नहीं होगा। इसमें ठहराव आ जाएगा। अगले एक दशक और उससे भी अधिक समय तक यह विस्तार नए रिएक्टरों के निर्माण पर कम और भारत के प्रथम चरण के दाबयुक्त भारी जल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) से प्रयुक्त ईंधन के पुनर्संसाधन पर अधिक निर्भर करेगा। भारत के प्रयुक्त ईंधन में कई टन अविभाजित प्लूटोनियम मौजूद है। इस सामग्री को प्रचलन में लाना ही पहले तीन रिएक्टरों से आगे एफबीआर विस्तार की गति निर्धारित करेगा। यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बुनियादी ढांचा अभी भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। तारापुर में एकीकृत परमाणु पुनर्चक्रण संयंत्र (इंटीग्रेटेड न्यूक्लियर रिसायकलिंग प्लांट–आईएनआरपी) क्षमता का विस्तार करेगा लेकिन इसके 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है और इसकी उत्पादन क्षमता केवल 3–4 और सभी एफबीआर की जरूरत पूरा कर पाएगा। इस बीच, एफबीआर ईंधन के पुनर्संसाधन के लिए निर्मित कल्पक्कम स्थित फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकिल फैसिलिटी (एफआरएफसीएफ) में 2030 तक विलंब हो गया है। यहां तक कि परिचालन में आने पर भी इसकी क्षमता केवल प्रारंभिक तीन रिएक्टरों के लिए ही निधारित है। जब तक पुनर्संसाधन क्षमता में पर्याप्त विस्तार नहीं किया जाता,

रिएक्टरों का अगला सेट संभवतरू 2045 के बाद ही शुरू हो पाएगा और थोरियम की ओर सार्थक परिवर्तन 2060 के बाद ही संभव हो सकेगा। भारत के पास इतना समय नहीं है। दो संरचनात्मक बदलावों ने समय सीमा को कम कर दिया है। पहला है ऊर्जा परिवर्तनय भारत को 2070 तक नेट–जीरो लक्ष्य को पूरा करने, औद्योगिक रूप से प्रतिस्पर्धी बने रहने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अगले दो दशकों के भीतर बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करना होगा। दूसरा है मांग की प्रकृतिरू कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय और हाइपरस्केल डेटा सेंटर मॉडल। इन केंद्रों को चौबीसों घंटे लगातार, उच्च घनत्व वाली बिजली की आवश्यकता होती है। अत्यधिक महंगे भंडारण के बिना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसी बिजली प्रदान नहीं कर सकते। परमाणु विखंडन ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जो स्वच्छ, हर मौसम में पर्याप्त मात्रा में बिजली प्रदान कर सकता है और यही कारण है कि दुनिया इसकी ओर लौट रही है। अमेरिका 2050 तक अपनी क्षमता को चार गुना बढ़ाकर 400 गीगावाट करना चाहता है जबकि चीन का लक्ष्य 500 गीगावाट है। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। इस विस्तार का अधिकांश हिस्सा कम से कम 2040 तक यूरेनियम आधारित होगा जो एक धीमा, महंगा और अपव्ययी मार्ग हैय और भारत के लिए, हथियारों से लैस आपूर्ति श्रृंखलाओं और अवरोधों के इस दौर में एक संभावित रणनीतिक जाल है। भारत का एफबीआर कार्यक्रम एक बड़ा लाभ है लेकिन तभी जब इसे अब से 2040 के बीच तेजी से बढ़ाया जाए अन्यथा भारत पीछे रह जाएगा। रूस अपनी प्रोरिव (ब्रेकथ्रू) परियोजना को आगे बढ़ा रहा है जो एक एकीकृत मॉडल है जिसमें लेड कूल्ड ब्रीडर (ब्रेस्ट–ओडी–300) को वहां स्थित ईंधन सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। यह भारत के कल्पक्कम मॉडल के समान है लेकिन इसे निर्यात के लिए डिजाइन किया गया है। चीन ने 2023 के अंत में अपने पहले वाणिज्यिक पैमाने के ब्रीडर सीएफआर–600 को चालू करके भारत को पीछे छोड़ दिया और इस वर्ष दूसरी इकाई भी चालू हो गई है। चीन ने मोल्टन सॉल्ट रिएक्टरों (एमएसआर) के मामले में भी वैश्विक स्तर पर बढ़त हासिल कर ली है जो थोरियम के उत्पादन के लिए ब्रीडर मार्ग को पूरी तरह से दरकिनार कर सकते हैं। टेरापावर, कोपेनहेगन एटॉमिक्स और मोल्टेक्स जैसी पश्चिमी स्टार्टअप कंपनियां भी थोरियम के उपयोग और अपशिष्ट में कमी लाने के लिए फास्ट रिएक्टर और एमएसआर (मल्टीपल स्केलर) बनाने की होड़ में लगी हैं। यदि इनमें से कोई भी मॉडल पहले सफल हो जाता है तो भारत के कार्यक्रम पर अपना रास्ता छोड़ने का दबाव पड़ेगा। हमारे अपने पीएचडब्ल्यूआर कार्यक्रम के साथ ऐसा ही हुआ क्योंकि यह समय पर सफल नहीं हो पाया इसलिए हमने कुडनकुलम में रूसी रिएक्टरों का सहारा लिया। एफबीआर कार्यक्रम के लिए भी यही जोखिम मौजूद है। भारत के विस्तार पर सबसे बड़ी बाधा विखंडनीय प्लूटोनियम भंडार है, विशेष रूप से 2035–2045 के बीच। वर्तमान में ब्रीडर कार्यक्रम सीमित संख्या में असुरक्षित रिएक्टरों से प्राप्त प्लूटोनियम पर निर्भर है। वहीं, भारत ने अपने सुरक्षित रिएक्टरों के लिए आयातित यूरेनियम से खर्च किया हुआ ईंधन जमा कर लिया है। यह महत्वपूर्ण प्लूटोनियम बेकार पड़ा है क्योंकि हमारे पास सुरक्षित पुनर्संसाधन की सुविधा नहीं है। इसका समाधान यह है कि नागरिक विस्तार को सैन्य कार्यक्रम से अलग किया जाए–जैसा कि एक दोहरी प्रणाली के माध्यम से भारत–अमेरिका परमाणु समझौते के तहत यूरेनियम प्राप्त करने के मामले में किया गया था।

हरी खाद-खेती में बढ़ेगा उत्पादन, मिट्टी की सेहत होगी बेहतर

धनंजय राठौर

आज के दौर में टिकाऊ खेती की ओर बढ़ना समय की मांग है। रसायनों के बोझ तले दबती मिट्टी को राहत देने के लिए हरी खाद एक बेहतरीन समाधान बनकर उभरी है। यह न केवल फसलों की पैदावार बढ़ाती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन की उर्वरता को भी सुरक्षित रखती है। मिट्टी बचेगी, तो किसान बचेगा और किसान बचेगा, तो देश समृद्ध होगा।

कृषि विभाग द्वारा किसानों को खेती में हरी खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और उत्पादन में सुधार लाने में मदद मिल सके। विभाग के अनुसार धान के खेतों में लगातार रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की गतिविधियां कम हो रही हैं और मिट्टी की संरचना भी प्रभावित हो रही है।

क्या है हरी खाद?

हरी खाद वह सहायक फसल है जिसे मुख्य फसल बोने से पहले खेत में उगाया जाता है और फूल आने की अवस्था में ही उसे हल चलाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। ढैंचा, सनई, लोबिया, मूंग और उड़द जैसी फसलें हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। हरी खाद के तहत कई फसलों का उपयोग किया जाता है जिनमें दलहनी और बिना दलहनी फसलें शामिल होती हैं। हरी खाद के लिए झाड़ियों और पेड़ों की पत्तियों, टहनियों को भी उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए विशेष रूप से ढैंचा फसलों का उपयोग किया जाता है। इन फसलों को खेतों में लगाकर भूमि में सुधार किया जाता है।

मिट्टी की सेहत में सुधार

हरी खाद का सबसे बड़ा प्रभाव मिट्टी की भौतिक और रासायनिक संरचना पर पड़ता है। यह मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों (ह्यूमस) की मात्रा को तेजी से बढ़ाती है। हरी खाद मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, जिससे हवा का संचार बढ़ता है और पौधों की जड़ें गहराई तक जा पाती हैं। इसके उपयोग से मिट्टी की पानी सोखने की शक्ति बढ़ जाती है, जो सूखे के समय फसलों के लिए जीवन रक्षक साबित होती है। उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी जब मिट्टी स्वस्थ होती है, तो उत्पादन का बढ़ना निश्चित है। हरी खाद के प्रयोग से पैदावार में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी जा सकती है। यूरिया और अन्य रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे किसान की फसल की लागत घटती है। मित्र कीटों से फसल का संरक्षण करता है। यह जमीन के भीतर लाभकारी सूक्ष्मजीवों और केंचुओं की संख्या बढ़ाने में मदद करती है। हरी खाद बनाने की सही विधि क्षेत्र की जलवायु के अनुसार सनई या ढैंचा का चुनाव करें। बुवाई का समय मानसून की शुरुआत (जून–जुलाई) इसके लिए सबसे उपयुक्त है। जब फसल लगभग 40–50 दिन की हो जाए और उसमें फूल आने लगें, तब उसे पाटा लगाकर या रोटावेटर की मदद से मिट्टी में मिला दें। पलटने के बाद 10–15 दिनों तक खेत में नमी बनाए रखें ताकि खाद अच्छी तरह सड़कर मिट्टी का हिस्सा बन जाए।हरी खाद के प्रयोग से बढ़ेगी आयहरी खाद केवल एक उर्वरक नहीं है, बल्कि यह मिट्टी का उपचार है। यदि किसान हर दूसरे या तीसरे साल अपने खेत में हरी खाद का प्रयोग करें, तो न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि हम समाज को रसायनों से मुक्त, शुद्ध और पौष्टिक अनाज भी उपलब्ध करा पाएंगे।कृषि के लिए एक वरदान हरी खाद हरी खाद का उपयोग कृषि के लिए एक वरदानष् के समान है। वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, ऐसे में हरी खाद प्राकृतिक तरीके से मिट्टी को पुनर्जीवित करने का सबसे सुलभ विकल्प है। कृषि विभाग द्वारा खरीफ फसल से पूर्व हरी खाद के बीज उपलब्ध कराने की भी पहल की जा रही है। इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से किसानों से मांग लेकर बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

नेपाल की अर्थव्यवस्था – संरचनात्मक चुनौतियां और सुधार की राह

अभिनव

चुनावी कवरेज लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक नीतियों की निरंतरता और निवेश वातावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। हाल के वर्षों में राजनीतिक परिवर्तन और नए दलों के उदय के बाद यह सवाल और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या इन बदलावों से अर्थव्यवस्था में कोई वास्तविक और स्थायी सुधार देखने को मिला है? नेपाल की अर्थव्यवस्था इस समय कई संरचनात्मक और नीतिगत चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। बढ़ता व्यापार घाटा, आयात पर अत्यधिक निर्भरता, सीमित निर्यात क्षमता और घटती राजस्व वृद्धि ने आर्थिक संतुलन को कमजोर किया है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव, सार्वजनिक खर्च में वृद्धि और उत्पादकता की धीमी गति ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। इसके साथ ही लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक नीतियों की निरंतरता और निवेश वातावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। हाल के वर्षों में राजनीतिक परिवर्तन और नए दलों के उदय के बाद यह सवाल और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या इन बदलावों से अर्थव्यवस्था में कोई वास्तविक और स्थायी सुधार देखने को मिला है? इन्हीं मुद्दों को समझने के लिए देशबन्धु के लिए कुमार अभिनव ने नेपाल के पूर्व वित्त मंत्री सुरेन्द्र पाण्डे से विशेष बातचीत की। नेपाल की अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? नेपाल की अर्थव्यवस्था इस समय गंभीर संरचनात्मक असंतुलन से गुजर रही है। देश की सबसे बड़ी समस्या अत्यधिक आयात निर्भरता और सीमित निर्यात क्षमता है, जिसके कारण व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्व प्रणाली भी स्थायी नहीं है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा आयात आधारित करों पर निर्भर करता है। जैसे–जैसे आयात बढ़ता है, राजस्व बढ़ता तो है, लेकिन यह दीर्घकालिक विकास का आधार नहीं बन सकता। साथ ही सार्वजनिक खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि उत्पादन, औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन की गति अपेक्षाकृत धीमी है। इससे आर्थिक असंतुलन और गहरा हो रहा है। राजनीतिक परिवर्तन बार–बार होने के बावजूद आर्थिक नीतियों में अपेक्षित स्थिरता नहीं आ पाई है। हर नई सरकार के साथ प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक योजनाएं प्रभावित होती हैं। इस नीति अस्थिरता के कारण निवेशकों का भरोसा कमजोर होता है और बड़े आर्थिक सुधारों की गति धीमी पड़ जाती है। वर्तमान स्थिति को केवल संकट या केवल अवसर के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह संकट और संक्रमण दोनों का मिश्रण है। संकट इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, व्यापार घाटा बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा पर दबाव है। संक्रमण इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था धीरे–धीरे पारंपरिक ढांचे से आधुनिक और उत्पादन–आधारित प्रणाली की ओर बढ़ रही है। यदि सही नीतियां अपनाई जाएं तो यह स्थिति अवसरों में भी बदल सकती है।वर्तमान वित्तीय व्यवस्था दीर्घकाल में टिकाऊ नहीं है। सरकार का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि राजस्व वृद्धि धीमी है। इसके अलावा कर प्रणाली का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है, जिससे अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बनी रहती है। सीमा कर नीतियों के कारण कई आवश्यक वस्तुएं महंगी हो गई हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। सीमा क्षेत्रों में छोटे व्यापार प्रभावित हुए हैं और स्थानीय बाजारों की गतिविधि कमजोर हुई है। इसका सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर प्रभाव पड़ा है।जब कर दरें अधिक होती हैं और निगरानी कमजोर होती है, तो अवैध व्यापार की संभावना बढ़ जाती है। इससे सरकारी राजस्व का नुकसान होता है और स्थानीय व्यापारियों को असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। वैश्विक संघर्षों का सीधा असर नेपाल जैसी आयात–निर्भर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र में अस्थिरता के कारण तेल की कीमतें बढ़ती हैं। इससे परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है और आम जनता की क्रय शक्ति प्रभावित होती है।विदेश से आने वाली आय में गिरावट का क्या प्रभाव होगा? विदेशी आय नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यदि इसमें गिरावट आती है तो विदेशी मुद्रा भंडार पर गंभीर दबाव पड़ेगा। इससे आयात क्षमता घटेगी, बैंकिंग प्रणाली और भुगतान संतुलन प्रभावित होगा तथा बेरोजगारी और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। –नेपाल को भारत और चीन के बीच कैसे संतुलन बनाना चाहिए? भारतीय संस्कृति पत्रिका नेपाल को संतुलित और व्यावहारिक नीति अपनानी चाहिए। किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचना आवश्यक है। दोनों देशों से निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। राजनीतिक अस्थिरता का निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? राजनीतिक अस्थिरता निवेशकों के विश्वास को कमजोर करती है। नीति में अनिश्चितता के कारण दीर्घकालिक निवेश प्रभावित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप विकास परियोजनाएं धीमी पड़ जाती हैं और आर्थिक विकास की गति कम हो जाती है। नेपाल के लिए मुख्य नीतिगत सुधार क्या होने चाहिए नेपाल को उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करनी चाहिए। आयात निर्भरता को कम करके घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही रोजगार सृजन, कृषि और औद्योगिक विकास, और आंतरिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान देना होगा ताकि अर्थव्यवस्था अधिक संतुलित और मजबूत बन सके। (अतिरिक्त दृष्टिकोण । दीपेन्द्र अधिकारी के विचार) इस बातचीत के बाद अंतरराष्ट्रीय मामलों के शोधकर्ता एवं विश्लेषक दीपेन्द्र अधिकारी ने नेपाल की आर्थिक दिशा पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि नेपाल को आर्थिक कूटनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि व्यापार घाटा कम किया जा सके। केवल निर्भरता नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क और परस्पर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि धार्मिक और पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा अर्जन बढ़ाया जा सकता है साथ ही जलविद्युत क्षेत्र में निवेश को तेज करना चाहिए ताकि ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़े और निर्यात की संभावनाएं मजबूत हों। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल को अपनी सॉफ्ट पावर को मजबूत करना चाहिए, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति बेहतर हो सके।

नन्हे कदम गढ़ेंगें सशक्त भारत का भविष्य–आंगनबाड़ी केंद्रों का नया रूप, नई दिशा

डॉ. दानेश्वरी संभाकर

देश का भविष्य जिन नन्हे कदमों से आगे बढ़ता है, वे आज आंगनबाड़ी केंद्रों में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ संवर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र कभी केवल पोषण और देखभाल तक सीमित माने जाते थे, वे अब प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता और ग्रामीण रोजगार के समन्वित मॉडल के रूप में विकसित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर, सूरजपुर, रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, मुंगेली और नारायणपुर जैसे जिलें में दिख रहा यह सकारात्मक बदलाव अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणास्रोत बन रहा है। भवन ही बन गया शिक्षक रू शबिल्डिंग ऐज लर्निंग एड्य की अभिनव पहल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से निर्मित आधुनिक आंगनबाड़ी भवनों ने सीखने के साधन के रूप में भवन की अवधारणा को साकार रूप दिया है। लगभग 11.69 लाख रुपए की लागत से बने इन भवनों में दीवारों, फर्श, सीढ़ियों और खुले स्थानों को शिक्षण सामग्री के रूप में विकसित किया गया है। रंग–बिरंगी चित्रकारी के माध्यम से बच्चों को हिंदी–अंग्रेजी वर्णमाला, अंक, आकृतियाँ, दिशाएँ, जीव–जंतु और स्थानीय परिवेश की जानकारी सहजता से मिल रही है। अब हर दीवारें बोलती हैं, हर कोना सिखाता है आंगनबाड़ी स्वयं एक जीवंत पाठशाला बन गई है। धमतरी का श्बाला मॉडल्य रू सीखने का नया अनुभव धमतरी जिले में बाला मॉडल ने प्रारंभिक बाल शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाने की दिशा में उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मनरेगा, आईसीडीएस और 15वें वित्त आयोग के सहयोग से 81 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, जिनमें से 51 पूर्ण हो चुके हैं। ग्राम उड़ेंना का केंद्र इस बदलाव की जीवंत तस्वीर है, जहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति कमार वर्ग के बच्चे खेल–खेल में सीख रहे हैं। दीवारों पर स्थानीय संस्कृति, गणितीय अवधारणाएँ और भाषा चार्ट, फर्श पर रंग और आकार तथा सीढ़ियों पर गिनती जैसे नवाचार बच्चों में जिज्ञासा और सीखने की रुचि को बढ़ा रहे हैं। शिक्षा के साथ रोजगार का मजबूत आधार मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण ने दोहरा लाभ दिया है। एक ओर गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना विकसित हुई है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिले हैं। इससे परिवारों की आय में वृद्धि हुई है और ग्रामीणों के पलायन में कमी आई है। इस प्रकार आंगनबाड़ी केवल बच्चों के विकास का केंद्र नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का माध्यम भी बन गया है। खेल–खेल में सीखता बचपन, खिलखिलाता माहौल महासमुंद के शहरी क्षेत्रों से लेकर नारायणपुर के दूरस्थ वनांचल तक, आंगनबाड़ी केंद्रों में नया वातावरण साफ दिखाई देता है। आकर्षक दीवारें, शैक्षणिक चार्ट, कविताएँ और खेल सामग्री ने इन्हें आधुनिक प्ले–स्कूल जैसा रूप दे दिया है। बच्चे अब उत्साह के साथ केंद्र आते हैं और भाषा, गणित व व्यवहारिक ज्ञान को आनंदपूर्वक सीखते हैं। पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता का केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र अब बच्चों के साथ–साथ गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरियों के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके हैं। यहाँ पोषण, पूरक पोषण आहार टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण और परामर्श सेवाएँ नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। दीवारों पर लिखे संदेश जितनी बेहतर वजन रेखा, उतना स्वस्थ बच्चा और लड़का–लड़की एक समान सामाजिक परिवर्तन का संदेश भी दे रही हैं। कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, नोनी सुरक्षा योजना और महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो रहा है। इससे माताओं और बालिकाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। स्वच्छता, सुरक्षा और जनभागीदारी आरओ जल, स्वच्छ रसोई, सुरक्षित खेलघर और नियमित साफ–सफाई ने केंद्रों को बाल–अनुकूल बनाया है। महतारी समितियों की सक्रिय भागीदारी से बच्चों की उपस्थिति और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सशक्त भारत की मजबूत नींव आंगनबाड़ी केंद्रों का यह परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पोषण अभियान के लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर साकार कर रहा है। 11.69 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्रत्येक केंद्र अब बच्चों के सर्वांगीण विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण रोजगार का समन्वित मॉडल बन चुका है। आज आंगनबाड़ी केंद्र वास्तव में बच्चों की पहली पाठशाला बन गए हैं, जहाँ शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और रोजगार मिलकर एक सशक्त, समावेशी और विकसित भारत की नींव रख रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक–कल्याणकारी नीतियों और जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है जीत : गिरीश चंद्र यादव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । यूपी के जौनपुर में पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्यों के चुनावी परिणामों के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही बढ़त को लेकर जहां संबंधित राज्यों में जश्न का माहौल है, वहीं जौनपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सोमवार को बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने सीहीपुर स्थित जिला कार्यालय पर पटाखे फोड़कर और मिठाइयां तथा झालमुड़ी बांटकर खुशी जाहिर की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लहराते हुए जोरदार नारेबाजी की और एक–दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। पूरे कार्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक–कल्याणकारी नीतियों और जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पार्टी के लिए गर्व का क्षण बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पार्टी को मिला जनसमर्थन आगामी चुनावों के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगा। उन्होंने दावा किया कि जनता ने भाजपा की विचारधारा पर विश्वास जताते हुए समर्थन दिया है और आने वाले समय में पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। नेताओं ने तीनों राज्यों की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जनादेश विकास और सुशासन के पक्ष में है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने पांच राज्यों में जाकर पार्टी के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। भाजपा नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी खुद को अजेय मानती थी, आज उसे जनता ने जवाब दे दिया है। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना विपक्ष की पुरानी आदत है, लेकिन इससे जनादेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी है।

दूल्हे की हत्या में शामिल चार आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, तीन घायल, मुख्य आरोपी फरार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । यूपी के जौनपुर में सरायख्वाजा थाना अंतर्गत दूल्हे आजाद बिंद की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोमवार सुबह खेतासराय थाना क्षेत्र के बादशाही बाजार में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान तीन आरोपियों को गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में सोमवार को जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात नकाबपोश बदमाशों ने बरात लेकर जा रहे दूल्हे आजाद बिंद की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। मुठभेड़ में घायल आरोपियों की पहचान संदहा निवासी कुशल मिश्रा, अमितेश मिश्रा और खुटहन निवासी विकास के रूप में हुई है, जबकि एक अन्य आरोपी खुटहन निवासी अजय यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, इस मामले का मुख्य आरोपी आजमगढ़ निवासी प्रदीप बिंद अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। एसपी ग्रामीण ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं, पुलिस अधीक्षक डॉ. कुंवर अनुपम सिंह ने कहा कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक के पिता ने इस हत्या के पीछे पुराने विवाद को कारण बताया है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इस बीच रविवार को परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार करने से मना करने पर और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजनों को जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र सिंहध्राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव,सांसद धनंजय सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें समझा–बुझाकर अंतिम संस्कार के लिए राजी किया। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर मामले पर्दाफाश किया जाएगा।

दूल्हा हत्याकांड तीन मुख्य आरोपियों पर इनाम दोगुना

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । खेतासराय क्षेत्र में 1 मई को हुए दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के तीन मुख्य फरार अभियुक्तों पर पुलिस ने इनाम की राशि दोगुनी कर दी है। अब इन तीनों पर 25 हजार रुपये की जगह 50–50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी प्रदीप बिंद पुत्र सोमारू बिंद निवासी चिकसाँवा, आजमगढ़, रवि यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी सोंधी, जौनपुर और भोले राजभर पुत्र जियालाल निवासी जपटापुर, जौनपुर वारदात के बाद से फरार चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के उद्देश्य से इनाम की राशि बढ़ाई गई है। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल अन्य अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य अभियुक्तों की तलाश में आसपास के जिलों में भी संपर्क साधा जा रहा है। वाराणसी परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा इन तीनों वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। थाना खेतासराय में इनके विरुद्ध मु0अ0सं0–90/2026, धारा– 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज है।

गौराबादशाहपुर में पुलिस मुठभेड़, एक बदमाश घायल गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । यूपी के जौनपुर के गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और एक आईफोन बरामद किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत की गई।इस मामले में सोमवार को जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी केराकत अजीत सिंह चौहान ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी केराकत अजीत सिंह चौहान के पर्यवेक्षण में गौराबादशाहपुर पुलिस टीम 4 मई की रात चोरसंड मोड़ हाईवे के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दो संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार लिलहा मोड़ की ओर से आने वाले हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन चेकिंग शुरू की। आजमगढ़ की तरफ से आ रहे बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश की पहचान अजय यादव पुत्र अमरनाथ यादव, निवासी उडली, थाना सरायख्वाजा, जौनपुर के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने फरार साथी की पहचान अंकित यादव पुत्र मुन्ना लाल यादव, निवासी दशरथा, थाना गौराबादशाहपुर, जौनपुर के रूप में बताई। पुलिस के अनुसार, फरार आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मौके से पुलिस ने एक देशी तमंचा .315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक आईफोन बरामद किया है। घायल बदमाश को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोरसंड भेजा गया। इस संबंध में थाना गौराबादशाहपुर में एमएम आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार कॉम्बिंग अभियान चला

कैंट क्षेत्र में चोरी का खुलासा 3 शातिर चोर गिरफ्तार, 11.48 लाख नकद समेत जेवर बरामद

लखनऊ, (संवाददाता)। थाना कैंट क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बड़ी मात्रा में नकदी, आभूषण और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है।प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल 2026 को रणजीत सिंह निवासी ओल्ड विक्टोरिया लाइन, कैंट ने थाना कैंट में अपने घर में अलमारी का ताला तोड़कर आभूषण और कीमती सामान चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस संबंध में मुकदमा संख्या 40ध26 धारा 305() बीएनएस के तहत मामला पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक राकेश कुमार चौरसिया द्वारा की जा रही थी।घटना के खुलासे के लिए थाना कैंट पुलिस और सर्विलांस मध्य जोन की संयुक्त टीम लगातार प्रयासरत थी। इसी क्रम में 1 मई 2026 को पुलिस टीम ने पतारसी और सुरागरसी के आधार पर लोको चौराहे के पास पानी की टंकी के समीप तीन संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में अपने नाम आदिल कुरैशी (22 वर्ष) निवासी आजाद मोहाल सदर कैंट, सूरज सरोज (19 वर्ष) निवासी शहीद नगर हुसैनगंज और सोहेल (22 वर्ष) निवासी शहीद नगर हुसैनगंज बताया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चोरी से संबंधित एक चौन, एक अंगूठी, एक पायल, एक चांदी का सिक्का, सूर्या ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट का सदस्यता कार्ड तथा 11,48,000 रुपये नगद बरामद किए गए।

गिरफ्तारी का कारण न बताना गैरकानूनी, हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया 10 लाख हर्जाना

लखनऊ, (संवाददाता)। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध घोषित कर तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए थे। कोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन मानते हुए यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का हर्जाना लगाया। कोर्ट ने सरकार को यह राशि चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को दोषी अधिकारियों से इसकी वसूली करने की छूट भी दी है। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह फैसला उन्नाव में गिरफ्तार मनोज कुमार की ओर से उसके पुत्र मुदित द्वारा दाखिल याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य है कि गिरफ्तारी के आधार लिखित में दिए जाएं। दरअसल, मनोज कुमार को 27 जनवरी 2026 को थाना असीवन, जिला उन्नाव में दर्ज एक मुकदमे के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के कारण वाले कॉलम में केवल मुकदमे की अपराध संख्या दर्ज थी। इसके बाद 28 जनवरी को मजिस्ट्रेट ने आरोपी की रिमांड मंजूर कर ली। याचिकाकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को हाईकोर्ट में चुनौती दी और तर्क दिया कि उसे गिरफ्तारी के आधार लिखित में नहीं बताए गए, जो एक अनिवार्य संविधानिक सुरक्षा का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हाए रिमांड आदेश रद्द कर दिया और कहा कि यदि व्यक्ति किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। साथ ही सरकार को दोषी अधिकारियों से हर्जाने की वसूली करने की छूट दी है।

संक्षिप्त खबरें

ठाकुरगंज में सड़क किनारे अज्ञात युवक का शव मिला, शिनाख्त के प्रयास जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक अज्ञात युवक का शव सड़क किनारे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 मई 2026 को करीब 1रू30 बजे थाना ठाकुरगंज पुलिस को सूचना मिली कि श्याम मोटर्स के सामने डिवाइडर पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां एक लगभग 30 वर्षीय अज्ञात पुरुष मृत अवस्था में पाया गया।पुलिस ने मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की और पहचान के लिए केजीएमयू मर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है।पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कराने के प्रयास जारी हैं। साथ ही, मौत के कारणों का पता लगाने के लिए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

मई दिवस पर पत्रकारों की आवाज बुलंद, ईपीएफ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर केंद्र से होगी वार्ता

लखनऊ, (संवाददाता)। मई दिवस के अवसर पर यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि वह 3 मई को केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीया से मुलाकात कर ईपीएफ की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यूनियन द्वारा दिए गए ज्ञापन के आधार पर यह पहल की जा रही है, जिसमें न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किए जाने की मांग प्रमुख है।अनिल राजभर ने यूनियन पदाधिकारियों से अपील की कि वे प्रदेश स्तर पर एक बड़ा संवाद कार्यक्रम आयोजित करें, जिसमें विभिन्न जिलों के पत्रकार शामिल हों। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे कार्यक्रम में वह स्वयं दो से तीन घंटे का समय देंगे और पत्रकारों की समस्याओं को विस्तार से सुनेंगे।यूनियन के प्रादेशिक अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में पत्रकारों के लिए पेंशन व्यवस्था, पत्रकार सुरक्षा कानून, पीजीआई में सभी श्रमजीवी पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा, प्राथमिकता पर भूखंड आवंटन, आर्थिक सहायता की स्थायी व्यवस्था और ट्रेन किराए में छूट बहाल करने की मांग उठाई।विशिष्ट अतिथि विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकारिता के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन पत्रकारों को निर्भीक होकर सच्चाई का पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज के वंचित और पीड़ित वर्ग की आवाज हैं, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी चाहिए।यूपी प्रेस क्लब के अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह ने पत्रकारिता के बदलते स्वरूप पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब स्वस्थ आलोचना भी जोखिम भरा काम बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और खबरों को रोका जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर संकेत हैं।हिंद मजदूर महासभा के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर मिश्र ने कहा कि पत्रकारों के वेज बोर्ड का गठन बंद हो गया है ।

जनगणना कार्यो में लगे स्कूलों के शिक्षक, बंद होने लगे विद्यालय

लखनऊ, (संवाददाता)। देश–प्रदेश में जनगणना से जुड़ी प्रक्रिया गति पकड़ रही है। इसके लिए जहां प्रशिक्षण हो रहे हैं तो

मकान सूचीकरण व मकानों की गणना भी शुरू हो गई है। जनगणना से जुड़े काम में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रगणक व पर्यवेक्षक बनाया जा रहा है। इसका सीधा असर विद्यालयों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कुछ जगह पर विद्यालय बंद हो गए हैं। जनगणना के लिए अप्रैल के अंत में अधिकतर जिलों में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। कई जगह पर सुबह से शाम तक प्रशिक्षण में शिक्षकों को बुलाया गया। इसका असर विद्यालयों की पढ़ाई व स्कूल चलो अभियान आदि पर सीधा पड़ा है। खुद फर्रुखाबाद के बीएसए ने डीएम को पत्र भेजकर कहा है कि मकानों की गणना में सभी शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को लगा दिया गया है। इसके कारण विद्यालय बंद हो गए हैं। ऐसे में प्रधानाध्यापक को इस काम से मुक्त किया जाए। इसी तरह बरेली व उन्नाव आदि जिलों के बीएसए ने अपने यहां डीएम व जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि सभी शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना में लगाने से विद्यालय बंद हो गए हैं। इससे स्कूल चलो अभियान, नए पंजीकरण, एमडीएम का वितरण आदि योजनाओं भी प्रभावित हो रही हैं। इन्होंने प्रधान शिक्षक व इंचार्ज शिक्षक को ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है। ताकि विद्यालय का कार्य व पढ़ाई सुचारू की जा सके। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि पहले परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को लगभग एक साल एसआईआर में लगा दिया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें बोर्ड परीक्षा में लगा दिया गया। परिषदीय विद्यालयों की पढ़ाई पूरी तरह चौपट रही। सिर्फ परीक्षाओं के लिए शिक्षकों को दस दिन का समय दिया गया। अब जब नया सत्र शुरू हो रहा है। सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल चलो अभियान चल रहे हैं। इसमें बच्चों को जोड़ने की जगह शिक्षकों को जनगणना में लगा दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि और भी विभाग है, उनके कर्मचारियों को इस काम में लगाया जाए। कई कम मानदेय वाले कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी ड्यूटी इस काम में लगे। ऐसे में विद्यालयों की पढ़ाई भी नहीं प्रभावित होगी और काम भी हो जाएगा। शिक्षकों व बीएसए ने बताया कि इस ड्यूटी में एक ही विद्यालय में काम करने वाले 4200 ग्रेड पे वाले शिक्षक को सुपरवाइजर और 4800 व 4600 ग्रेड पे वाले शिक्षक को प्रगणक बनाया गया है। उन्होंने मांग की ड्यूटी को संशोधित करते हुए वरिष्ठता को ध्यान में रखकर शिक्षकों को सुपरवाइजर व प्रगणक बनाया जाए। शिक्षकों की ड्यूटी के लिखित आदेश जारी किए जाएं।

जनेश्वर इन्क्लेव की 11वीं मंजिल से कूदकर युवक की मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के थाना गुडम्बा क्षेत्र स्थित कुर्सी रोड के जनेश्वर इन्क्लेव में गुरुवार रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। 11वीं मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।पुलिस के अनुसार 30 अप्रैल 2026 की रात करीब 8रू45 बजे सूचना मिली कि जनेश्वर इन्क्लेव की 11वीं मंजिल से एक युवक नीचे गिर गया है। सूचना मिलते ही थाना गुडम्बा पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि एक युवक गंभीर हालत में परिसर के नीचे पड़ा हुआ है। तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।मृतक की पहचान प्रबल जैन (31 वर्ष) पुत्र उमेश जैन, निवासी महमूदाबाद जनपद सीतापुर के रूप में हुई है। वह वर्तमान में अपनी पत्नी के साथ जनेश्वर इन्क्लेव के डी–ब्लॉक स्थित फ्लैट संख्या 1102 में किराए पर रह रहे थे, जो ओमप्रकाश श्रीवास्तव के नाम पर है।मौके पर मौजूद मृतक की पत्नी के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि प्रबल जैन ने 11वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की है। बताया गया कि मृतक प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता था, जबकि उसकी पत्नी सुलतानपुर रोड स्थित फीनिक्स प्लासियो मॉल में फ्लोर मैनेजर के पद पर कार्यरत है।

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिकों को समर्पित कई कार्यक्रम हुए

लखनऊ, (संवाददाता)। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस (मजदूर दिवस) के अवसर पर शुक्रवार को विभिन्न सरकारी, निजी और सामाजिक संस्थाओं की ओर से श्रमिकों के सम्मान, स्वास्थ्य और कल्याण को समर्पित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान श्रमिकों के योगदान को सराहा गया और उनके अधिकारों, सुरक्षा तथा सामाजिक सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर, संवाद कार्यक्रम, सम्मान समारोह और जरूरतमंद श्रमिकों को भोजन व आवश्यक सामग्री वितरण जैसे आयोजन किए गए। इन आयोजनों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि श्रमिक केवल कार्यबल नहीं, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जिनके सम्मान और कल्याण से ही समग्र विकास संभव है। चक गंजरिया स्थित पराग डेयरी फैक्टरी में शुक्रवार को श्रमिक सम्मान समारोह हुआ। मुख्य अतिथि पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने श्रमिकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की नींव हमारे श्रमिक ही हैं। दुग्ध क्षेत्र में भी श्रमिकों की मेहनत से उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और 'पराग' ब्रांड को नई पहचान मिल रही है। उन्होंने प्लांट का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि डेयरी को पूरी क्षमता के साथ पेशेवर ढंग से संचालित किया जाए। अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने कहा कि श्रमिक किसी भी संस्था की रीढ़ होते हैं और उनके बिना उत्पादन संभव नहीं है। कार्यक्रम में कई श्रमिकों को सम्मानित किया गया। वहीं, मंत्री धर्मपाल सिंह ने बख्शी का तालाब स्थित अकोहरी कान्हा गौशाला में गोवंश की विधिवत पूजा–अर्चना की। गोशाला में प्रतिदिन गोवंशों की सेवा में संलग्न गौसेवकों को सम्मानित भी किया। गोसेवकों और भूसा दानदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और पौधरोपण किया। शहर में सीवर प्रबंधन का काम देखने वाली निजी कंपनी सुएज इंडिया की ओर से अपनी बात, अपनों के साथ' संवाद श्रृंखला की शुरुआत की गई। परियोजना निदेशक राजेश मठपाल ने बताया कि कंपनी की ओर से कर्मचारियों को राशन किट का वितरण भी किया गया। सफाई का काम करने वाली निजी कंपनी रामकी (लखनऊ स्वच्छता अभियान) ने निजी अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। रामकी के प्रोजेक्ट

हेड अभय रंजन ने बताया कि इसमें 600 से अधिक वाहन चालकों एवं कर्मचारियों का समग्र स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। पात्र कर्मचारियों का आयुष्मान कार्ड के लिए पंजीकरण भी किया गया। – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ताड़ीखाना स्थित पलटन छावनी आश्रय गृह में श्रमिक संवाद कार्यक्रम हुआ। विज्ञान फाउंडेशन के सहयोग से हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने की। केजीएमयू के एसपीएम विभाग की अध्यक्ष प्रो. मोनिका अग्रवाल के नेतृत्व में सरोजनीनगर के नटकुर गांव में स्वास्थ्य शिविर लगा। केजीएमयू के गोद लिए गए नटकुर गांव में हुए कार्यक्रम में प्रो. मोनिका अग्रवाल ने एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) संक्रमण और उससे होने वाले गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया। नौ किशोरियों का एचपीवी वैक्सीन से टीकाकरण किया गया। आलमबाग नहर के लेबर चौक पर दिहाड़ी किचन के माध्यम से श्रमिकों को भरपेट भोजन कराया गया। बदलाव रू एक कदम शिक्षा की ओर... संस्था की ओर से नियमित रूप से ऐसे श्रमिकों को भोजन कराया जाता है जो दूरदराज के क्षेत्रों से मजदूरी की तलाश में शहर आते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। संस्था के संचालक सोमनाथ कश्यप ने बताया कि विगत 10 वर्षों से दिहाडी मजदूर भाइयों के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अजय त्रिपाठी मुन्ना ने कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंबेडकरनगर वार्ड में सफाई कर्मचारियों व श्रमिकों माला पहनाकर व उपहार देकर सम्मानित किया गया। वन विभाग की ओर से कुकरैल रेंज स्थित मौल श्री प्रेक्षागृह में श्रमिक सम्मान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। मुख्य अतिथि डीएफओ सितांशु पांडेय ने श्रमिकों को सम्मानित भी किया। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की वाणिज्य शाखा और उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने अलग–अलग सभाएं कीं। एनआरएमयू संगठन के नेता विभूति मिश्रा मौजूद रहे।

मूलभूत समस्याएं बनी राम नगरी की प्रमुख पहचान

अयोध्या। पेयजल,पार्किंग,जाम,सीवर लाइन के नाम पर सड़कों पर खुदे गड्ढे,गंदगी सहित कई समस्याएं रामनगरी की प्रमुख पहचान बन चुकी हैं। जिसके चलते यहां के स्थानीय लोगों के अलावा दूसरे प्रदेशों तथा देश–विदेश से राम मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों पर दर्शन पूजन करने आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो इस समय राम मंदिर निर्माण की वेस्ट श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रामनगरी आ रही है जिसके चलते चार पहिया के वाहनों में बढ़ोतरी तो संभव ही है। वाहनों को खड़ा करने के लिए चाहे ट्रैफिक विभाग हो या फिर नगर निगम पर्याप्त संख्या में पार्किंग का भाव है जिसका पूरा–पूरा लाभ अवैध रूप से अयोध्या धाम में कुछ लोग उठा रहे हैं यह सभी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को खड़े करने के नाम पर मुंह मांगा पैसे भी वसूल रहे हैं। इसके अलावा बीच–बीच में यातायात पुलिस अन्य संबंधित विभागों के साथ लोगो को जाम से राहत देने के लिए बैठक तो कल ली जाती है लेकिन वह बैठक इस कमरे तक ही सीमित रहती है और परिणाम आज भी यही है कि शहर के सभी मार्गो चौराहा पर जाम ही जाम दिखाई देता है। इस समय सबसे बड़ी समस्या शहर के अधिकतर मार्गो मोहल्ले व कॉलोनियों की गलियों मैं सिविल लाइन बिछाने के लिए गड्ढे तो खुद दिए जाते हैं लेकिन उसे वैसा ही छोड़ दिया जाता है और आने वाले दिनों में खासकर बारिश के दौरान यहां पर रह रहे स्थानीय लोगों के अलावा इधर से गुजरने वाले लोगों को भी काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।इसी तरह कई समस्याएं रामनगरी में है परंतु इन गंभीर समस्याओं पर संबंधित विभाग चुप्पी साधे है जिसके चलते स्थानीय लोगों में उनके अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति आक्रोश प्राप्त है।

’बाढ़ पूर्व होने वाली अपनी विभागीय समस्त तैयारियां पूर्ण करा लें- जिलाधिकारी

रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव’

’हरदोई’ बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के तहत गठित बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक आज जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानन्द सभागार कलेक्ट्रेट में आहूत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने ऑनलाइन जुड़े उप जिलाधिकारी बिलग्राम, सवायजपुर, शाहाबाद से कहा कि समय से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना करें और नाव, नाविक, गोताखोरों को चिहिंत करें और उनके मोबाइल नम्बर सहित बुकलेट तैयार करायें तथा बाढ़ चौकियों को देख ले एवं बाढ़ पीड़ित लोगों व उनके पशुओं हेतु आश्रय स्थल चिहिंत कर लिये जाये। बैठक में जिलाधिकारी ने वन विभाग को निर्देश दिये कि कटान रोकने के लिए नदियों के किनारे–किनारे ऐसे वृक्ष लगवायें जो पानी के प्रवाह को रोक सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये कि बाढ़ प्रभावित गांवों में मेडिकल टीम की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं तथा पूर्ति विभाग खाद्यान्न एवं डीजल, मिट्टी तेल आदि व्यवस्था कराये तथा पीडब्लूडी द्वारा पूर्व में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्गो को शीघ्र ठीक करायें। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिये कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने वाले विद्यालयों को चिहिंत करे और बच्चों के पढ़ने के लिए स्थान चिहिंत कर लें। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश दिये कि बाढ़ आने के दौरान बाढ़ चौकियों एवं बाढ़ पीड़ितों के आश्रय स्थल पर विद्युत व्यवस्था बनाये रखें। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को गांव में भोजन बनवाकर प्रधान के माध्यम से वितरित कराया जायेगा। उन्होंने अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाढ़ पूर्व होने वाली अपनी विभागीय समस्त तैयारियां पूर्ण करा लें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रियंका सिंह, न्यायिक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी शारदा नहर, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बैठक सदर विधायक की अध्यक्षता मे सम्पन्न

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बंधित बैठक आयोजित किया गया रहे।बैठक मे उप कृषि निदेशक ने विधायक को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया।बताया कि इतना योजना के तहत जनपद में खरीफ मौसम में 2016 कृषकों को 18.03 लाख रुपया से फसल बीमा से लाभान्वित किया गया एवं रबी सीजन में 293 कृषकों का सर्वे किया गया जिसमें 30 कृषकों को 1.43 लाख रुपया

फसल बीमा से लाभान्वित किया जा रहा है।जिसमें आज 10 किसानों को चेक वितरण किया जा रहा है।जिसमें खरीफ मौसम में अरविंद कुमार यादव बीकापुर को 51934 रुपया, मधुबाला रुदौली को 56919 रुपया चंद्रकेतु मिश्रा अमानीगंज को 36584 रुपया राधेश्याम यादव को 41564 रुपया एवं सूर्यभान सिंह को 52598 रुपया फसल बीमा से लाभान्वित किया गया तथा रबी सीजन में संतोष कुमार पाण्डेय, सोहावल, 2442 रुपया, राम कुमार को 7341 रुपया शोभनाथ को 23127 रुपया, शुभांशु पाण्डेय 10736 रुपया एवं चंद्रप्रकाश पाण्डेय जी को 9214 रुपया का चेक विधायक ने दिया।इस मौके पर उप कृषि निदेशक, जिला उद्यान अधिकारी, मुख्य कार्यकारी मत्स्य अधिकारी, जिला सहायक आयुक्त एवं निबंधक सहकारीता,एवं जिला प्रबंधक अग्रणी बैंक, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे।

जांच समिति ने सौपी प्रभारी डीआईओएस को अपनी रिपोर्ट

अयोध्या।आजाद इंटर कॉलेज पलिया जगमोहन सिंह मिल्कीपुर में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में सभी विषयों के प्रयोगात्मक परीक्षा मे फेल करने के आरोप में कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ डीआईओएस डॉक्टर पवन कुमार तिवारी द्वारा गठित तीन सदस्य टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट तय सीमा के अंदर दो दिन के भीतर प्रभारी डीआईओएस ओंकार पाल को सौंप दिया है।28 अप्रैल को जारी पत्र के माध्यम से कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया था कि हाई स्कूल की पीड़ित छात्रा का सभी विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक त्रुटिवश कंप्यूटर पर फीड हो गया था।इस पत्र को संज्ञान मे लेते हुए प्रभारी डीआईओएस ने 1 मई को उक्त छात्रा के प्रयोगात्मक परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए पत्र को अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को भेज दिया है।इस मामले की जांच कर रहे जांच कमेटी के अध्यक्ष एडीआईओएस अश्वनी कुमार पांडे ने बताया उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट तय सीमा के अंदर प्रभारी डीआईओएस ओंकारपाल को सौंप दिया है।

कालका प्रसाद नारायण दास महाविद्यालय किठवा मे स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।सोमवार को कालका प्रसाद नारायण दास महाविद्यालय किठवा तहसील मिल्कीपुर में सामुदायिक केंद्र सोहावल एवं जिला क्षय रोग चिकित्सा अधिकारी अपनी टीम के साथ अध्यनरत छात्राओं एनसीसी कैडेट का स्वास्थ्य परीक्षण किया।जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप,जिला छह रोग अधिकारी डॉक्टर संदीप शुक्ला, सामुदायिक केंद्र सोहावल के अधीक्षक वर्मा डॉ संग्राम सिंह,स्टाफ नर्स दिव्या ने छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया दवा वितरित किया। इस मौके पर कुछ छात्रों को जुकाम की समस्या थी उनका एक–रे जांच की गई।डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय लू के प्रकोप एवं अन्य

संक्रमित रोगों से बचने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है।बच्चे उसके बारे में जानकारी रखें और बताए गए सावधानियां को बरते कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री जिला काउंसलर रेड क्रॉस काउंसलर आलोक तिवारी, सहित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अनूप कुमार, इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ प्रतिभा पाठक, रामकृष्ण, लेफ्टिनेंट डॉक्टर राकेश मौर्य, अतुल मिश्रा, वीरेंद्र मिश्रा, संजय दुबे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे

बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी की बैठक मे डीएम ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।सोमवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई।बैठक में जनपद के बाढ़ संभावित क्षेत्रों की तहसीलवार समीक्षा की गई।बैठक मे जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि संबंधित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी क्षेत्र में जाकर जमीनी

स्थिति का आकलन करें तथा स्थानीय निवासियों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझें। उन्होंने सरयू, तमसा, गोमती एवं बिशुही नदी के कटान प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।डीएम ने कहा कि सभी नालों एवं ड्रेनेज की समय से साफ–सफाई कराई जाए, जिससे जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके साथ ही बाढ़ चौकियों, राहत केंद्रों एवं राहत शिविरों को पूरी तरह क्रियाशील रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में पेयजल, विद्युत, चिकित्सा सुविधा, लाइफ जैकेट, गोताखोरों एवं नाविकों की सूची, आवश्यक वाहन एवं राहत किट आदि की समुचित व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाए।बैठक में अपर जिलाधिकारी (एफआर) अमित कुमार भट्ट,सीएमओ,सीवीओ व संबंधित एसडीएम तहसीलदार, अधिशासी अभियंता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन

अयोध्या। रविवार को पीएचसी एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया।मेले में कुल चिकित्सक 69, पैरामेडिकल 210, द्वारा सेवाएं प्रदान की गई।मेले में पुरुष मरीज 426., महिला मरीज 463, बच्चे 100, द्वारा अपना उपचार लाभ प्राप्त किया गया। मेले में आयुष्मान गोल्डन कार्ड बने 123, हेल्प डेस्क पर स्क्रीन हुए मरीज 151, कोविड टेस्ट 0 पॉजिटिव 0,आंख के मरीज 135, बुखार के

मरीज 144, सांस के मरीज 101, पेट के मरीज 172, शुगर के मरीज 166, चर्म रोग के मरीज 175, टीबी के सस्पेक्टेड मरीज 27, एनीमिया के 29, उच्च रक्तचाप के 73, प्रसव पूर्व जांच 170, कुपोषित 1, रेफर 103 लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई।

जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला के पास हुआ इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप का शुभारंभ

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। बलरामपुर मे एक नए पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ।इस मौके पर अयोध्या के संत बालमुकुंद दास जी महाराज,प्रभु दास जी महाराज व जयरामदास जी महाराज ने किया। बलरामपुर के उतरौला तहसील के मुख्यालय से बलरामपुर रोड पर 10 किलोमीटर के पास इंडियन ऑयल के नए पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ।इस पेट्रोल पंप की संरक्षिका डॉक्टर मीना सिंह प्रबंधन एवं व्यवस्थापक मयंक शेखर सिंह सीओ राघवेंद्र सिंह द्वारा

शुभारम्भ किया गया।उक्त अवसर पर परिवार सदस्य राणा रमेश विक्रम सिंह,अंकुर सिंह, राघवेंद्र विक्रम सिंह, एवं अनेक लोग मौजूद रहे।मौजूद व्यक्तियों का मानना है कि पेट्रोल पंप के खुलने से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। क्योंकि उसके आसपास कोई इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप नहीं था।जबकि पेट्रोल व डीजल किसानों व अन्य लोगो के लिए जरुरी है।

पिस्टल व वाहन समेत दो गिरफ्तार

अयोध्या।थाना पूरा कलंदर में तैनात प्रशिक्षु आईपीएस शुभम जैन के नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक थाना पूरा कलंदर मनोज शर्मा व चौकी प्रभारी गांजा अमरेंद्र सिंह ने दो आरोपियों को पिस्टल व वाहन के साथ गिरफ्तार किया।आरोपी अंकित दूबे पुत्र दिलीप दुबे निवासी ग्राम कोटवा थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी को ददेरा से जाने वाली नहर पुलिया कर्पूरी ठाकुर वार्ड नं0–14 कादीपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।जबकि दूसरे आरोपी सुरेश सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह उम्र करीब 42 वर्ष निवासी अशरफपुर थाना कैण्ट जनपद अयोध्या को गिरफ्तार किया।

राजकीय जिला पुस्तकालय अयोध्या में शोक सभा का आयोजन

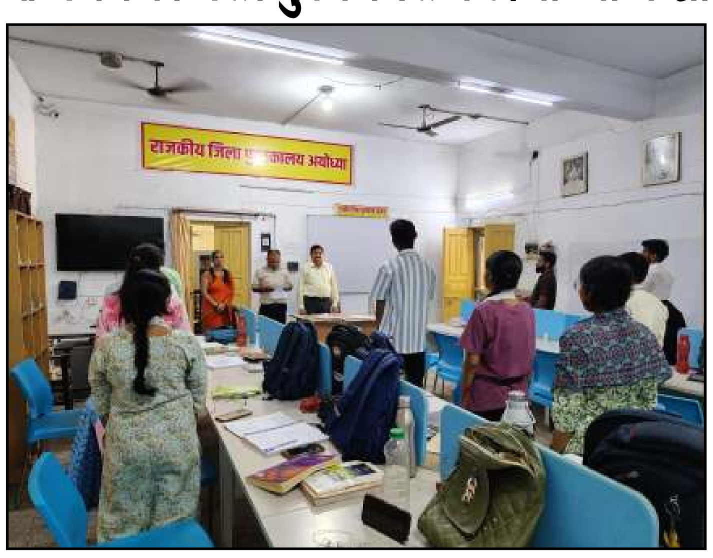

अयोध्या।जनपद गोरखपुर के डीआईओएस अमरकांत सिंह के आकस्मिक निधन पर रविवार को राजकीय जिला पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष अवनीश कुमार पांडे ने शोक सभा का आयोजन किया।इस मौके पर उन्होंने शोक संदेश पढ़ा।शोक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि डीआईओएस अमरकांत सिंह शिक्षा विभाग मे एक कर्मठ ईमानदार एवं कर्तव्य कर्तव्य निष्ठ व मृदुभाषी अधिकारी थे।जिनकी सेवाएं सदैव स्मरणीय रहेंगे।कहा वे अपने सादे विचार से अधिकारियो व कर्मियों का दिल जीत लेते है।इस मौके पर राजकीय जिला पुस्तकालय के सभी कर्मियों ने डीआईओएस अमर कांत सिंह के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतृप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त किया।शोक सभा में जिला मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ आलोक तिवारी, सदस्य जिला पुस्तकालय सत्य प्रकाश, मृदुला, कृष्ण कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे।

नजूल जमीन घोटाला मे प्रशासन ने रोका निर्माण

अयोध्या। जिले मे जमीन के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है।जहां थाना कैंट क्षेत्र के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित पराग डेयरी के पीछे एक कथित प्रॉपर्टी डीलर ताज मोहम्मद पर करीब 20 लोगों को नजूल (सरकारी) जमीन बेचने का आरोप लगा है।बताया जा रहा है कि आरोपी ने लोगों से करीब दो करोड़ रुपये वसूल कर फरार हो गया, जिससे पीड़ित परिवारों में आक्रोश फैल गया है।पीड़ितों के अनुसार, ताज मोहम्मद ने खुद को जमीन का वैध मालिक बताते हुए दावा किया कि यह उसके पूर्वजों की संपत्ति है और सभी दस्तावेज उसके पास मौजूद हैं। इसी भरोसे में आकर लोगों ने 10–10 लाख रुपये तक देकर प्लॉट खरीद लिए। कई लोगों ने तो अपने सपनों का घर बनाने के लिए निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया था।मामले का खुलासा तब हुआ जब नजूल विभाग की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और निर्माण को अवैध बताते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर अफरा–तफरी मच गई। गुस्साए पीड़ितों ने विरोध जताया और कुछ लोग बुलडोजर के सामने लेट गए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।प्रशासन ने फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है।एसडीएम (वित्त एवं राजस्व) ने पूरे मामले की जांच के लिए 15 दिन का समय तय किया है और सभी पीड़ितों से जमीन से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी आखिर कैसे हुई और इसमें और कौन–कौन लोग शामिल हैं। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपने नुकसान की भरपाई की मांग की है।

जमीन से सोने का सिक्का निकाला, महिला को लिया झांसे में– ठग लिए 4 लाख रुपये

गोरखपुर, (संवाददाता)। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में दिल्ली के जालसाज ने खुद को तंत्र–मंत्र का जानकार बताते हुए घर में अंग्रेजों के जमाने का गड़ा खजाना और उसे निकालने का झांसा देकर महिला से चार लाख रुपये ऐंठ लिए। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित महिला ने आरोपी इरशाद उर्फ रेहान के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिक दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गोरखनाथ क्षेत्र के रसूलपुर निवासी हस्सान नूरी के अनुसार, आरोपी इरशाद उर्फ रेहान ने उन्हें जमीन में गड़ा खजाना (सोना) निकालने का झांसा दिया। विश्वास जीतने के लिए वह उन्हें तिवारीपुर इलाके के डोमिनगढ़ ले गया, जहां उसने मेटल डिटेक्टर को जादू की छड़ी बताकर जमीन से सोने का सिक्का निकालकर दिखाया। इस चमत्कार को देखकर वह उसके झांसे में आ गईं और उनके मन में भी गड़ा धन पाने की लालसा जाग गई। इसके बाद आरोपी, महिला के घर पहुंचा और कुछ देर निरीक्षण करने के बाद दावा किया कि घर में अंग्रेजों के समय का भारी मात्रा में सोना–चांदी गड़ा हुआ है। इसे निकालने के लिए उसने चार लाख रुपये खर्च बताकर महिला को तैयार कर लिया। आरोप है कि उसने यह भी कहा कि विशेष पूजा की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिल्ली में एक विशेष व्यक्ति के पास जाना होगा। झांसे में आई महिला कर्ज लेकर आरोपी के साथ दिल्ली पहुंची। वहां एक युवक मास्क लगाकर आया,।

लता चौक पर महिला एसओ आशा शुक्ला के नेतृत्व मे महिला एसआई चेतना पाण्डेय ने महिलाओ को किया जागरूक

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।शुक्रवार को एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर तथा मिशन शक्ति फेज 5 के नोडल प्रभारी व एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी के निर्देश पर सीओ सिटी श्रीयेश त्रिपाठी की देखरेख मे महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के नेतृत्व मे लता चौक व आसपास महिला उप निरीक्षक चेतना पांडे ने महिला कांस्टेबल लक्ष्मी सोनी,पीआरडी साधना, माधुरी व महिला पुलिसकर्मियो के साथ महिलाओ को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक किया।इस मौके पर उन्होंने मिशन शक्ति अभियान फेज फाइव के तहत सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी देते हुए बताया कि जिससे कभी भी संकट के समय आप अपनी सुरक्षा कर सकती हैं।इस मौके पर उन्होंने महिलाओ व बालिकाओं से कहीं।उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए जहां एक तरफ उनके विकास को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण सुकन्या समृद्धि योजना सहित एक से बढ़कर एक कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चल रही हैं।इस मौके पर उन्होंने वहां पर मौजूद बालिकाओं को पंपलेट व बैनर पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना का अंदेशा हो तो बिना झिझक अपने नजदीकी पुलिस कर्मियों, महिला थाना तथा अपने परिजनों को फोन पर बताये।इस मौके पर उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।